Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तराखंड

फरवरी (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तराखंड **3**

- उत्तराखंड के मानसखंड की झाँकी को देश में पहला स्थान मिलने पर किया गया पुरस्कृत 3
- ट्रांसफर एक्ट की जगह नियमावली बनाकर शिक्षकों का तबादले पर अधिकार खत्म करने की तैयारी 3
- अब उत्तराखंड का हर शहर यूआईडीएफ से बनेगा स्मार्ट 4
- रेल परियोजनाओं के लिये उत्तराखंड को 5004 करोड़ रुपए की सौगात 4
- उत्तराखंड में बनेगा कैंसर नियंत्रण बोर्ड 5
- हल्द्वानी में प्रदेश के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन 5
- उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश 2023 का अनुमोदन 6
- देहरादून में हुआ देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कॉन्ग्रेस का आयोजन 6
- सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड देशभर में 14वें स्थान पर 7
- मुख्यमंत्री ने किया 06 नये पुलिस थानों एवं 20 पुलिस चौकियों का उद्घाटन 8
- मुख्यमंत्री अंत्योदय नि:शुल्क गैस रिफिल योजना का शुंभारभ 8
- वाहन खरीद नीति 2023 को कैबिनेट की मंजूरी 8
- मंत्रिमंडल ने 'उत्तराखंड मिलेट मिशन' योजना को दी मंजूरी 9
- पिथौरागढ़ में होगा भारत-उज्बेकिस्तान की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास 10
- प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप संशोधित नीति को मंजूरी दी 10
- काली नदी पर बने दो अंतर्राष्ट्रीय झूलापुल शुरू 10
- औली में 23 से 26 तक प्रस्तावित नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप रद्द 11
- उदयपुर के सराड़ा उपखंड में कृषि उपज मंडी की शीघ्र घोषणा होगी 11
- क्विक रिस्पांस टीम के लिये वन विभाग जारी करेगा एसओपी 12
- राज्य सरकार ने दी चार नई नीतियों को मंजूरी 12
- भारत-उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास 'दुस्तलिक' पिथौरागढ़ में शुरू 13
- गोवा-केरल की तर्ज पर उत्तराखंड में तैयार होगा पर्यटन पुलिस का ढाँचा 13
- 'मुख्यमंत्री उत्थान' और 'ज्ञानकोष योजना' 14
- अनमैंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर 14
- उत्तराखंड के दो सिपाहियों को मिला प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक 15
- यमुनोत्री रोप-वे निर्माण के लिये हुआ अनुबंध 15
- उत्तराखंड की चार नदियों में पाँच साल खनन कार्य के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति 16
- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं की तर्ज पर अब भोजन माताओं को भी मिलेगी सम्मान राशि 17
- काशी विश्वनाथ की तर्ज पर हरकी पौड़ी कॉरिडोर 17
- एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये योजनाओं पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने की तैयारी 18
- उत्तराखंड के ऊर्जा ज़रूरतों के आकलन की जिम्मेदारी अब अमेरिकी संस्था को 18
- प्रदेश में अनाथ बच्चों के लिये बनेगा देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक 19

नोट :

उत्तराखंड

उत्तराखंड के मानसखंड की झाँकी को देश में पहला स्थान मिलने पर किया गया पुरस्कृत

चर्चा में क्यों ?

31 जनवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में उत्तराखंड की झाँकी मानसखंड को प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिये केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पुरस्कार प्रदान किया। राज्य की ओर से सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।

प्रमुख बिंदु

- राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड की झाँकी को देश में पहला स्थान मिलने पर देश, विदेश के लोग मानसखंड के साथ ही उत्तराखंड की लोक संस्कृति से भी परिचित होंगे।
- इस अवसर पर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन के बाद मानसखंड पर आधारित झाँकी प्रस्तावित की गई थी।
- उन्होंने बताया कि कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड राज्य की ओर से मानसखंड की झाँकी में 18 कलाकारों के दल ने अपनी प्रस्तुति दी थी। झाँकी का थीम सांग 'जय हो कुमाऊँ, जय हो गढ़वाल'को पिथौरागढ़ के प्रसिद्ध जनकवि जनार्दन उप्रेती ने लिखा था। सौरभ मैठाणी और साथियों ने इसे सुर दिया था। इस थीम गीत के निर्माता पहाड़ी दगड़िया, देहरादून थे।
- सूचना महानिदेशक ने बताया कि श्री केदारनाथ एवं श्री बदरीनाथ की तर्ज पर कुमाऊँ के पौराणिक मंदिरों के लिये मुख्यमंत्री के निर्देश पर मानसखंड मंदिर माला मिशन योजना पर भी काम किया जा रहा है। इससे इन प्रमुख मंदिरों का विकास होना है। पहले चरण में करीब दो दर्जन से अधिक मंदिरों को इसमें शामिल किया गया है।
- इनमें जागेश्वर महादेव, चितई गोलज्यू मंदिर, सूर्यदेव मंदिर, नंदादेवी मंदिर कसारदेवी मंदिर, झांकर सैम मंदिर, पाताल भुवनेश्वर, हाटकालिका मंदिर, मोस्टमाणु मंदिर, बेरीनाग मंदिर, मलेनाथ मंदिर, थालकेदार मंदिर, बागनाथ महादेव, बैजनाथ मंदिर, कोट भ्रामरी मंदिर, पाताल रुद्रेश्वर गुफा, गोल्ज्यू मंदिर, निकट गोरलचौड मैदान, पूर्णागिरी मंदिर, वारही देवी मंदिर देवीधुरा, रीठा मीठा साहिब, नैनादेवी मंदिर, गर्जियादेवी मंदिर, कैंचीधाम, चौती (बाल सुंदरी) मंदिर, अटरिया देवी मंदिर व नानकमत्ता साहिब प्रमुख रूप से शामिल किये गए हैं।

ट्रांसफर एक्ट की जगह नियमावली बनाकर शिक्षकों का तबादले पर अधिकार खत्म करने की तैयारी

चर्चा में क्यों ?

31 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादलों के लिये एक्ट की जगह नियमावली बनाकर शिक्षकों के तबादले के अधिकार को खत्म करने की तैयारी की जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि शासन की ओर से सचिव समिति के पास हरियाणा की तर्ज पर बन रही नियमावली का जो ड्राफ्ट रखा जाना है, उसमें स्पष्ट लिखा है तबादला शिक्षक का अधिकार नहीं माना जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग में पारदर्शी तबादले राज्य गठन के बाद से सरकारों के लिये चुनौती बने रहे हैं। मनमाने तबादलों को लेकर राज्य सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं। यही वजह रही कि सरकार ने शिक्षकों के तबादलों के लिये वर्ष 2012 में बनी तबादला नीति को खत्म कर वर्ष 2017 में तबादला एक्ट बनाया, जिसे शिक्षा विभाग के साथ ही सभी विभागों के लिये वर्ष 2018 से लागू किया गया, लेकिन सरकार फिर नियमावली बनाने जा रही है।

नोट :

- शिक्षा विभाग की ओर से अब इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसमें शिक्षकों के तबादलों के लिये स्कूलों को दो क्षेत्रों (पर्वतीय और मैदानी) में बाँटा गया है। ड्राफ्ट में स्पष्ट किया गया है कि तबादलों के लिये ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें अनिवार्य तबादले शिक्षकों के गुणांकों के आधार पर वरीयता क्रम में उपलब्ध खाली पदों पर किये जाएंगे। जबकि अनुरोध के आधार पर विशेष श्रेणी के शिक्षकों के तबादले होंगे।
- जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रघुवीर पुंडीर ने बताया कि एक्ट से दुर्गम से सुगम क्षेत्र के स्कूल में तबादले की उम्मीद रहती है। यदि एक्ट की जगह नियमावली बना दी गई तो अधिकारियों और मंत्रियों की परिक्रमा करने वाले चहेते शिक्षक ही सुविधाजनक स्कूलों में तबादला पाएंगे।

अब उत्तराखंड का हर शहर यूआईडीएफ से बनेगा स्मार्ट

चर्चा में क्यों ?

2 फरवरी, 2023 को उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव आनंदवर्द्धन ने बताया कि केंद्र सरकार ने आम बजट में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (यूआईडीएफ) बनाने का एलान किया है, जिससे देहरादून स्मार्ट सिटी के बाद अब प्रदेश का हर शहर स्मार्ट बन सकेगा।

प्रमुख बिंदु

- अपर मुख्य सचिव आनंदवर्द्धन ने बताया कि यूआईडीएफ बनने से नाबार्ड की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की योजनाओं को न्यूनतम ब्याज दरों पर लोन मिल सकेगा।
- गौरतलब है कि अभी तक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिये न्यूनतम दरों पर लोन मिलता था। शहरी क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या का दबाव और संसाधनों की आवश्यकता के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना काफी खर्चीला साबित होता था। एजेंसियों से महँगी ब्याज दरों पर लोन लेना पड़ता था, जिसकी भरपाई भी चुनौतीपूर्ण काम था।
- आनंदवर्द्धन ने बताया कि टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिये बनने वाला यूआईडीएफ राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के अंतर्गत संचालित होगा।
- यूआईडीएफ से शहरी क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आएगा तथा तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की चुनौतियों से पार पाया जा सकेगा।

रेल परियोजनाओं के लिये उत्तराखंड को 5004 करोड़ रुपए की सौगात

चर्चा में क्यों ?

3 फरवरी, 2023 को उत्तराखंड के देहरादून मंडल के रेल प्रबंधक अजय नंदन ने बताया कि आम बजट 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में रेल प्रोजेक्ट्स के लिये 5004 करोड़ रुपए की सौगात दी है।

प्रमुख बिंदु

- मंडल के रेल प्रबंधक अजय नंदन ने बताया कि इससे जहाँ सामरिक महत्त्व की ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट में तेजी आएगी वहीं हरिद्वार, देहरादून रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। नौ अन्य स्टेशनों पर भी यात्रियों को आधुनिक सुविधाएँ मिलेंगी।
- रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 5004 करोड़ रुपये की यह रकम वर्ष 2009-14 की तुलना में 27 गुना अधिक है। वर्ष 2009-14 में यह महज 187 करोड़ रुपए था। इस बजट से देहरादून और हरिद्वार को वर्ल्ड क्लास स्टेशन के तौर पर विकसित करने की योजना है।
- मंडल रेल प्रबंधक अजय नंदन ने बताया कि उत्तराखंड का बजट बढ़ाए जाने के बाद ऋषिकेश- कर्णप्रयाग रेल लाइन समेत अन्य परियोजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने में मदद मिलेगी।
- उन्होंने बताया कि हरिद्वार और देहरादून स्टेशन के ठीक ऊपर 45 से लेकर 117 मीटर चौड़ा रूप टॉप प्लाजा बनेगा। इसमें खानपान के साथ विश्राम करने की सुविधा होगी। यात्रियों के साथ इसका इस्तेमाल आम लोग भी कर सकेंगे।
- प्रदेश के काशीपुर, लालकुआँ, रामनगर, टनकपुर, किच्छा, काठगोदाम, हर्रावाला, रुड़की और कोटद्वार रेलवे स्टेशनों पर लिफ्ट के साथ स्वचालित सीढ़ियाँ भी लगाई जाएंगी। बिल्डिंग का कायाकल्प, प्लेटफार्म का विस्तारीकरण, आधुनिक शौचालय, यात्री विश्राम गृह, वाटर एटीएम बूथ आदि का निर्माण होगा।

नोट :

- अजय नंदन ने बताया कि देश में 750 रेलवे स्टेशनों पर 'एक स्टेशन-एक उत्पाद'योजना लागू की गई है। इसमें हरिद्वार और देहरादून स्टेशन शामिल हैं। यहाँ गैर सरकारी संगठन और संस्थाएँ स्थानीय उत्पाद के स्टॉल लगाती हैं।
- उन्होंने बताया कि 'अमृत भारत योजना' के तहत कोटद्वार रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का संचालन पुरानी सिग्नल प्रणाली की जगह कंप्यूटर के जरिये किया जाएगा। इसके लिये रेलवे की ओर से निर्माण कार्य किये जा रहे हैं।
- मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि अब बहुप्रतीक्षित रुड़की-देवबंद रेल परियोजना के निर्माण कार्यों को भी गति मिलेगी। रुड़की रेलवे स्टेशन पर दो नए प्लेटफार्म का निर्माण करने के साथ ही नए फुट ओवर ब्रिज, स्वचालित सीढ़ी का निर्माण किया जाएगा।
- विदित है कि रुड़की ऐतिहासिक स्टेशनों में शामिल है। यह देश का पहला स्टेशन है, जहाँ वर्ष 1852 में पहली बार मालगाड़ी का संचालन किया गया था।
- अजय नंदन ने बताया कि हर्रावाला रेलवे स्टेशन को 105 करोड़ की लागत से टर्मिनल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ से 24 कोच वाली ट्रेनों का संचालन करने के लिये प्लेटफॉर्म का विस्तारीकरण कर नए प्लेटफार्म बनाए जाएंगे। देहरादून से चलने वाली कई ट्रेनों का संचालन भी हर्रावाला से ही किया जाएगा। हर्रावाला से हरिद्वार के बीच पड़ने वाले डोईवाला, रायवाला और कांसरो जैसे स्टेशनों के कायाकल्प पर भी 150 करोड़ खर्च होंगे।

उत्तराखंड में बनेगा कैंसर नियंत्रण बोर्ड

चर्चा में क्यों ?

3 फरवरी, 2023 को उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि जानलेवा बीमारी कैंसर से बचाव और उपचार के लिये उत्तराखंड में कैंसर नियंत्रण बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके लिये शासन स्तर पर कवायद चल रही है।

प्रमुख बिंदु

- स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश के सभी जनपदों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ), एएनएम, आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जा रही है, जिससे समय से कैंसर रोगियों का इलाज हो सके।
- गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में 49 लाख लोगों की मुख कैंसर, 2.79 लाख स्तन कैंसर और 34 हजार लोगों की सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की गई है।
- स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि कैंसर नियंत्रण बोर्ड बनने के बाद कैंसर से ग्रसित मरीजों का डाटा प्रबंधन और शुरुआती दौर में रोग की पहचान और उपचार के लिये प्रभावी रणनीति पर काम किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित राष्ट्रीय कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, स्ट्रोक नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस), गैर संचारी रोगों जैसे कैंसर व अन्य के रोकथाम के लिये काम किया जा रहा है।
- विदित है कि वर्तमान में प्रदेश में कैंसर मरीजों को कीमोथैरेपी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी और चमोली में कैंसर डे केयर सेंटर संचालित हैं।
- इसके अलावा बागेश्वर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, ऊधमसिंह नगर कैंसर डे केयर सेंटर स्थापित किये जाएंगे।

हल्द्वानी में प्रदेश के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

7 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के हल्द्वानी -काठगोदाम नगर निगम में सबसे बड़े 28 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और लेगेसी अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इन दोनों प्लांट की लागत क्रमश: 58 करोड़ रुपए और 3 करोड़ रुपए है।

नोट :

- हल्द्वानी और आसपास के शहरों में स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिये हल्द्वानी के गौलापार में इन दोनों संयंत्रों का निर्माण किया गया है।
- इन संयंत्रों का निर्माण अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजना के तहत किया जा रहा है।
- हल्द्वानी में एसटीपी के संचालन से गौला नदी को प्रदूषण से बचाया जा सकेगा और किसान संयंत्र से प्राप्त अपशिष्ट का उपयोग जैविक खाद के रूप में कर सकेंगे।
- राज्य सरकार ने गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषित करने वाले 132 नालों में सीवेज प्लांट लगाए हैं। वर्तमान में 11 सीवरेज प्लांट का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कई अन्य घोषणाएँ भी कीं। उन्होंने वन्य जीव एवं पर्यटन के लिये हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर के निर्माण हेतु आवश्यकता अनुसार धनराशि उपलब्ध कराने की घोषणा की। साथ ही उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिये हल्द्वानी में नशामुक्ति केंद्र खोलने की योजना की भी घोषणा की।

उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश 2023 का अनुमोदन

चर्चा में क्यों ?

9 फरवरी, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता एवं शुचिता को सुनिश्चित करने के लिये उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश 2023 का अनुमोदन किया है।

प्रमुख बिंदु

- इस अध्यादेश के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं-
  - इस अध्यादेश में दोषियों के विरूद्ध सख्त प्रावधान किये गए हैं। यदि कोई व्यक्ति, प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, प्रबंध तंत्र, कोचिंग संस्थान इत्यादि अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिये आजीवन कारावास तक की सजा तथा दस करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
  - यदि कोई व्यक्ति संगठित रूप से परीक्षा कराने वाली संस्था के साथ षडयंत्र करता है तो आजीवन कारावास तक की सजा एवं 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
  - यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा में स्वयं नकल करते हुए या अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिये तीन वर्ष के कारावास व न्यूनतम पाँच लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
  - यदि वह परीक्षार्थी दोबारा अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पुन: दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ न्यूनतम दस वर्ष के कारावास तथा न्यूनतम 10 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
  - यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते हुए पाया जाता है तो आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से दो से पाँच वर्ष के लिये डिबार करने तथा दोषसिद्ध ठहराए जाने की दशा में दस वर्ष के लिये समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार किये जाने का प्रावधान किया गया है।
  - यदि कोई परीक्षार्थी दोबारा नकल करते हुए पाया जाता है तो क्रमश: पाँच से दस वर्ष के लिये तथा आजीवन समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार किये जाने का प्रावधान किया गया है। अनुचित साधनों के इस्तेमाल से अर्जित संपति की कुर्की की जाएगी।
  - इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध संज्ञेय, गैर जमानती एवं अशमनीय होगा।

देहरादून में हुआ देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कॉन्ग्रेस का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

10 फरवरी, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूकॉस्ट, परिसर, विज्ञान धाम, झाझरा में तीन दिवसीय 17वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कॉन्ग्रेस 2023 के अंतर्गत देश के 'प्रथम ग्रामीण विज्ञान कॉन्ग्रेस'का शुभारंभ किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस विज्ञान कॉन्ग्रेस का लक्ष्य उत्तराखंड के गाँवो का समुचित विकास करना है।
- इस आयोजन के माध्यम से ग्रामीण संस्कृति, कृषि, ग्रामीण पर्यटन और व्यंजन जैसे विभिन्न विषयों पर संवाद स्थापित किये जाएंगे।
- एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सार्थक करने और राज्य के समेकित विकास को गति प्रदान करने में यह आयोजन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हाइड्रोपोनिक यूनिट, क्यू आर कोड आधारित जैव विविधता पार्क एवं प्राईड ऑफ उत्तराखंड एक्सपो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया साथ ही इस अवसर पर ग्रामीण विज्ञान कॉन्ग्रेस, उत्तराखंड ग्राम्य विकास यात्रा एवं विज्ञान पर चर्चा पुस्तकों का विमोचन भी किया गया।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वैज्ञानिकों को विज्ञान पुरोधा सम्मान एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया।

सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड देशभर में 14वें स्थान पर

चर्चा में क्यों ?

12 फरवरी को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट (Social Progress Index Report) में उत्तराखंड 100 में से 19 अंक प्राप्त कर देशभर में 14वें स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

- सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार नागरिकों को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने में 78 अंक के साथ गोवा शीर्ष पर है। वहीं असम सबसे आखिरी स्थान पर है जिसे महज 36.14 अंक ही मिले हैं।
- हिमालयी राज्यों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 12 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पाँचवें स्थान पर है जबकि मिज़ोरम को पहला स्थान मिला है।
- बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का स्तर पता लगाने के लिये प्रत्येक राज्य को चार मापदंडो पर परखा गया है। इन मापदंड में भी कई बिंदु समाहित किये गए हैं। ये चार मापदंड निम्न है-
  - पोषण और बुनियादी स्वास्थ्य सुरक्षा: कितने प्रतिशत नागरिकों को पर्याप्त भोजन और बुनियादी चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल रहा है।
  - पानी और स्वच्छता: नागरिकों को मिल रहे पेयजल की गुणवत्ता कैसी है और उनके परिवेश में स्वच्छता का कितना ध्यान रखा जा रहा है।
  - आवास: कितने प्रतिशत नागरिकों को बुनियादी उपयोगिताओं के साथ आवास की सुविधा मिली है। इसमें उन्हें सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिला।
  - व्यक्तिगत सुरक्षा: यह भी परखा गया कि नागरिकों की सुरक्षा का स्तर क्या है। इसके लिये अपराध के स्तर के साथ सड़क सुरक्षा का भी अध्ययन किया गया।
- उत्तराखंड को तय मानकों में मिले अंक- पोषण और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा-30, जल और स्वच्छता-67.94, आवास-62.77 तथा व्यक्तिगत सुरक्षा-67.74 अंक।
- हिमालयी राज्यों को मिले अंक- मिज़ोरम-06, सिक्किम-65.65, हिमाचल प्रदेश-65.32, नगालैंड- 63.26, उत्तराखंड-62.19, जम्मू-कश्मीर-59.39, अरुणाचल प्रदेश- 57.72, मणिपुर -56.53, त्रिपुरा-50.80, मेघालय-46.61 तथा असम-36.14 अंक।
- तय मानकों के आधार पर हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड आवास के मामले में मिज़ोरम से बेहतर है। इसमें उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है, जबकि मिज़ोरम चौथे स्थान पर।
- पेयजल की गुणवत्ता और स्वच्छता के मामले में भी उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। व्यक्तिगत सुरक्षा के मामले में उत्तराखंड को चौथा स्थान मिला है।
- सबसे खराब स्थिति पोषण और बुनियादी स्वास्थ्य सुरक्षा की है, इसमें उत्तराखंड आठवें पायदान पर है।
- नागरिकों को बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के मामले में देहरादून ज़िला प्रदेश में शीर्ष पर है। इसके लिये देहरादून को निर्धारित 100 में से 71 अंक मिले हैं।

नोट :

मुख्यमंत्री ने किया 06 नये पुलिस थानों एवं 20 पुलिस चौकियों का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

13 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से राज्य में 06 नये पुलिस थानों एवं 20 पुलिस चौकियों का वर्चुअल उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इन 6 थानों में 661 ग्राम एवं 20 चौकियों में 696 ग्राम शामिल हैं। ये क्षेत्र पहले राजस्व पुलिस के अधीन थे, अब इनमें नियमित पुलिस की व्यवस्था की गई है।
- जिन 06 नये पुलिस थानों का उद्घाटन किया गया उनमें पौड़ी में थाना यमकेश्वर, टिहरी में थाना छाम, चमोली में थाना घाट, नैनीताल में थाना खनस्यूँ एवं अल्मोड़ा में थाना देघाट एवं धौलछीना शामिल हैं।
- वहीं जिन 20 नई चौकियों का उद्घाटन किया उनमें देहरादून में लाखामंडल, पौड़ी में बीरोखाल, टिहरी में गजा, कांडीखाल एवं चमियाला, चमोली में नौटी, नारायणबगड़ एवं उर्गम, रूद्रप्रयाग में चौपता एवं दुर्गाधार, उत्तरकाशी में सांकरी एवं धौंतरी, नैनीताल में औखलकांडा, धानाचूली, हेड़ाखाल एवं धारी, अल्मोड़ा में मजखाली, जागेश्वर एवं भौनखाल तथा चंपावत में बाराकोट शामिल हैं।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकास एवं व्यवस्थाओं में परिवर्तन के साथ राज्य के जिन क्षेत्रों में राजस्व पुलिस की तैनाती की गई थी उन जगहों पर उनमें चरणबद्ध तरीके से नियमित पुलिस की व्यवस्था की जा रही है।
- साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री राज्य बनाने, स्वच्छता अभियान एवं सामाजिक सरोकारों के अन्य कार्यों में भी उत्तराखंड पुलिस को लगातार कार्य करना होगा।
- गौरतलब है कि पुलिस व्यवस्था राज्य की कानून-व्यवस्था का दर्पण होती है। सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को बनाने की पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी होती है।

मुख्यमंत्री अंत्योदय नि:शुल्क गैस रिफिल योजना का शुंभारभ

चर्चा में क्यों ?

12 फरवरी, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल के कंडोलिया मैदान से मुख्यमंत्री अंत्योदय नि:शुल्क गैस रिफिल योजना का शुंभारभ किया गया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने 23 महिलाओं को गैस रिफिल का लाभ देकर योजना की शुरूआत की।
- इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को 01 वर्ष में 03 नि:शुल्क गैस रिफिल का लाभ दिया जाएगा तथा पूरे प्रदेश में लगभग 1 लाख 76 हज़ार अंत्योदय कार्ड-धारकों को इसका लाभ मिलेगा।
- मुख्यमंत्री अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना से उत्तराखड की महिलाओं के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन आएगा। इस योजना से धुआँ रहित भारत की परिकल्पना को साकार करने का बल मिलेगा और महिलाओं का जीवन अधिक स्वस्थ्य और आसान हो जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि पूर्व में मुख्यमंत्री ने सस्ते गल्ले की दुकान से सस्ती दरों पर चीनी व नमक को भी वितरित करने तथा तेल व मसालों को सस्ती दरों पर देने की योजना के लिये भी कार्ययोजना बनाने की बात कही थी। इसी परिप्रेक्ष्य में यह योजना शुरू की गई है।

वाहन खरीद नीति 2023 को कैबिनेट की मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

15 फरवरी, 2023 को उत्तराखंड के परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने बताया कि प्रदेश के विशिष्ट, अति विशिष्ट महानुभावों और विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों के लिये सरकारी वाहन खरीदने की नीति 2023 पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने बताया कि उत्तराखंड के मंत्रियों के लिये अब 35 लाख कीमत तक के ई-वाहन और 25 लाख तक की सामान्य वाहन खरीदे जा सकेंगे। इससे प्रदेश में 31 मार्च से पहले 1500 वाहन खरीदने की राह भी आसान हो गई है।
- परिवहन सचिव ने बताया कि वाहनों की खरीद के नए दामों के अलावा निजी वाहन उपयोग करने पर किराया की प्रतिपूर्ति और आउटसोर्स वाहनों के लिये भी किराए की दरों में बढ़ोतरी की गई है।
- निजी वाहन की किराया प्रतिपूर्ति में बी श्रेणी के लिये किराए की दर 23 हज़ार से बढ़ाकर 41,272 रुपए प्रतिमाह, सी श्रेणी में 20,000 से बढ़ाकर 38,544 रुपए, डी श्रेणी में 17,000 से बढ़ाकर 33,007 रुपए, ई श्रेणी में 17,000 से बढ़ाकर 27,430 रुपए प्रतिमाह की दर तय की गई है।
- किराए पर लिये गए वाहनों के लिये भी बी श्रेणी में किराया 41,100 से बढ़ाकर 48,498 रुपए, सी श्रेणी में 37,740 से बढ़ाकर 44,533 रुपए, डी-ई श्रेणी के लिये 27,000 से बढ़ाकर 31,860 रुपए हो जाएगा।
- विभिन्न श्रेणियों में बढ़े दाम-
  - श्रेणी ए- मंत्री, मुख्य सचिव, हाईकोर्ट के जज, आयोगों के अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ), डीजीपी, प्रमुख सचिव व समकक्ष- 15 लाख (पुरानी दर), 25 लाख (नई दर), 35 लाख (ई-वाहन की मूल्य सीमा)।
  - श्रेणी बी- सचिव, एचओडी, मंडलायुक्त, आईजी, प्रमुख वन संरक्षक, ज़िला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम अध्यक्ष व समकक्ष- 12 लाख (पुरानी दर), 20 लाख (नई दर), 25 लाख (ई-वाहन की मूल्य सीमा)।
  - श्रेणी सी- अपर सचिव, अपर विभागाध्यक्ष, डीआईजी, अपर पीसीसीएफ, डीएम, एसएसपी- 08 लाख (पुरानी दर), 18 लाख (नई दर), 20 लाख (ई-वाहन की मूल्य सीमा)।
  - श्रेणी डी- विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष, सीडीओ, मंडल-संभाग स्तर अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष व समकक्ष- 06 लाख (पुरानी दर), 14 लाख (नई दर), 16 लाख (ई-वाहन की मूल्य सीमा)।
  - श्रेणी ई- नगर पंचायत अध्यक्ष, ज़िला स्तरीय अधिकारी, अन्य अधिकृत अधिकारी जिन्हें वाहन अनुमन्य हो- 06 लाख (पुरानी दर) 10 लाख (नई दर) 12 लाख (ई-वाहन की मूल्य सीमा)।

मंत्रिमंडल ने 'उत्तराखंड मिलेट मिशन' योजना को दी मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

16 फरवरी, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने प्रदेश के पारंपरिक अनाज मंडुवा, झंगोरा को बढ़ावा देने के लिये 'उत्तराखंड मिलेट मिशन' योजना को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने पहली बार 'उत्तराखंड मिलेट मिशन'को हरी झंडी दी है। अंत्योदय योजना में हर राशनकार्ड पर एक किलो मंडुवा एक रुपए में मिलेगा। इसके अलावा मिड डे मील में झंगोरा भी दिया जाएगा।
- इस योजना को देहरादून, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार व नैनीताल ज़िले में शुरू किया जाएगा।
- योजना में मंडुवे (कोदा) का उत्पादन और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिये 73 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस राशि में से 53 करोड़ कृषि विभाग और 20 करोड़ की राशि सहकारी समितियों को दिया जाएगा।
- योजना के तहत सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों से मंडुवा 78 रुपए प्रति किलो खरीदा जाएगा।
- गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बजट में श्री अन्न योजना की घोषणा की है। इससे मोटे अनाजों को बढ़ावा मिलेगा।

नोट :

पिथौरागढ़ में होगा भारत-उज्बेकिस्तान की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास

चर्चा में क्यों ?

16 फरवरी, 2023 को सेना से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के पिथौरागढ़ सैन्य क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास (दस्तलिक) 20 फरवरी से शुरू होगा जो पाँच मार्च तक चलेगा। इसमें दोनों देशों के 45-45 जवान प्रतिभाग करेंगे।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार इस संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिक अपने-अपने कौशल और अनुभव को साझा करेंगे। दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियाँ पहाड़ी, ग्रामीण या फिर शहरी क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने का अभ्यास करेंगी।
- इस संयुक्त अभ्यास से दोनों देशों के सैन्य संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस संयुक्त अभ्यास में दोनों देशों के 90 जवान शामिल होंगे।
- गौरतलब है कि इससे पहले पिथौरागढ़ में वर्ष 2019 में भारत और कजाकिस्तान का जबकि वर्ष 2021 में भारत और नेपाल की सेना के जवानों का संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था।

प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप संशोधित नीति को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों ?

16 फरवरी, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने स्टार्टअप संशोधित नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति में सरकार ने आगामी पाँच साल के भीतर एक हज़ार स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य रखा है, इसके अलावा स्टार्टअप को दिये जाने वाले प्रोत्साहन व वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी की है।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिये 200 करोड़ रुपए का वेंचर फंड तैयार करेगी। इससे नवाचार आइडिया पर बिजनेस शुरू करने के लिये युवा उद्यमियों को सरकारी स्तर पर फंड मिल सकेगा। अभी तक स्टार्टअप को वेंचर निवेशक ही वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते थे।
- ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार में विजेता नवाचार आइडिया को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को 50 हज़ार रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए किया गया है। इसके अलावा यदि कोई स्टार्टअप कंपनी क्रय वरीयता नीति में पंजीकरण होती है तो सरकारी विभाग 10 लाख रुपए तक सीधे स्टार्टअप से खरीद कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को एक साल तक निशुल्क इन्क्यूबेशन की सुविधा भी दी जाएगी।
- स्टार्टअप कंपनी के उत्पाद को ट्रेक मार्क लेने के लिये सरकार की ओर से प्रति ट्रेडमार्क 10 हज़ार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा दो उत्पादों को पेटेंट कराने के लिये 1 से 5 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता मिलेगी। उत्पादों का डिजाइन कराने के लिये नीति में 10 हज़ार रुपए की सहायता देने की व्यवस्था की गई है।
- नीति में सरकार ने मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिये 10 लाख रुपए तक एकमुश्त सीड फंडिंग की व्यवस्था की है। महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग, ग्रामीण क्षेत्रों के नवाचार स्टार्टअप को 5 लाख की राशि मिलेगी।
- सरकार द्वारा नई नीति में स्कूल व कॉलेजों के साथ ही ज़िला स्तर पर नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे नये नवाचार आइडिया को सरकार प्रोत्साहित करेगी।

काली नदी पर बने दो अंतर्राष्ट्रीय झूलापुल शुरू

चर्चा में क्यों ?

16 फरवरी, 2023 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले की डीएम रीना जोशी और नेपाल, दार्चूला के सीडीओ दीर्घराज उपाध्याय ने संयुक्त रूप से भारत व नेपाल के बीच सीमांत तहसील धारचूला से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में काली नदी पर बने दो अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का शुभारंभ किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इन पुलों से दोनों देशों की 10 हज़ार से अधिक की आबादी को लाभ मिलेगा। दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियाँ भी बढ़ेंगी और रोटी-बेटी के रिश्ते मजबूत होंगे।
- काली नदी पर गस्कू में बने झूला पुल की लंबाई लगभग 140 मीटर और जयकोट में बने मलघट्या झूला पुल की लंबाई लगभग 135 मीटर है। दोनों पुलों की भार क्षमता 42 टन है।
- दोनों स्थानों पर पुल बनने से भारत के गाँव जयकोट, पांगला, गस्कू और नेपाल के माल, रापला, दुमलिंग, सुसारपानी सहित कई अन्य गाँवों की लगभग 10 हज़ार से अधिक की आबादी को लाभ मिलेगा।
- इन स्थानों पर पुल नहीं होने से दोनों देशों के लोगों को शादी ब्याह और अन्य शुभ अवसरों पर लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। बारिश के समय काली नदी को नेपाल के लोग तार, ड्रम और ट्यूब के जरिये आर-पार करते थे। पुल बनने से जोखिम कम हो जाएगा।
- गौरतलब है कि दोनों पुलों के बनने से पिथौरागढ़ ज़िले में काली नदी पर भारत और नेपाल के बीच पुलों की संख्या 11 हो गई है। वर्तमान में झूलाघाट, डौड़ा, द्वालीसेरा, जौलजीबी, बलुवाकोट, धारचूला, तिगड़म रोंगती नाला, बड़ू-जुम्मा, मलघट्या जयकोट, गस्कू-माल, सीता पुल शामिल हैं।

औली में 23 से 26 तक प्रस्तावित नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप रद्द

चर्चा में क्यों ?

16 फरवरी, 2023 को स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव प्रवीण शर्मा ने बताया कि बर्फ न होने के कारण चमोली ज़िले के औली में 23 से 26 फरवरी तक प्रस्तावित नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप रद्द कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- प्रवीण शर्मा ने बताया कि इस संबंध में स्की एवं स्नो बोर्ड उत्तराखंड ने स्की एवं स्नो बोर्ड इंडिया की सभी संबद्ध इकाईयों को सूचना दे दी है।
- उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य सरकार ने नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप की पूरी तैयारियाँ कर रखी थीं, लेकिन मौसम के साथ न देने और कम बर्फबारी के कारण ये खेल रद्द करने पड़े हैं।
- विदित है कि पिछले वर्ष तक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र औली बर्फ से ढका रहता था और पर्यटकों की भीड़ औली में बनी रहती थी, लेकिन इस बार न्यू ईयर में भी बर्फबारी बहुत कम या न के बराबर देखने को मिली। हालाँकि, नए साल पर स्थानीय लोग कयास लगा रहे थे कि औली में बर्फबारी बढ़ेगी और नेशनल स्कीइंग प्रतियोगिता होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
- गौरतलब है कि औली भारत का प्रमुख स्की स्थल है। मूलरूप से अर्धसैनिक बेस के रूप में विकसित औली की स्कीइंग ढलान पर्यटकों और पेशेवरों के बीच समानरूप से लोकप्रिय है। सर्दियों में औली कई स्नो एडवेंचर इवेंट्स का आयोजन करता है।
- लगभग 2,800 मीटर की ऊँचाई पर स्थित और ओक व शंकुधारी जंगलों से घिरा औली भारत की कुछ सबसे ऊँची चोटियों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें देश की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सबसे ऊँची चोटी नंदा देवी (7,816 मीटर) भी शामिल है।
- यह हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे सहित नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार भी है। गोरसन बुग्याल, पंगेरचुल्ला समिट और तपोवन जैसे लोकप्रिय ट्रैकिंग स्थलों तक औली के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।
- औली के अलावा उत्तराखंड में दयारा बुग्याल, मुनस्यारी और मुंडाली जैसे कई अन्य स्कीइंग स्थल हैं।

उदयपुर के सराड़ा उपखंड में कृषि उपज मंडी की शीघ्र घोषणा होगी

चर्चा में क्यों ?

17 फरवरी, 2023 को राजस्थान के कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने विधानसभा में कहा कि राज्य में मंडी निर्माण के द्वितीय चरण में उदयपुर ज़िले के सराड़ा उपखंड में कृषि उपज मंडी बनाने की घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही चावंड में भी भूमि प्राप्त होते ही गौण मंडी बनवा दी जायेगी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गत 4 वर्षों में राज्य में 88 मंडियाँ घोषित की गई थीं, लेकिन बीच में नए कानून बनने के बाद प्रक्रिया धीमी हो गई थी।
- अब विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से प्रथम चरण में 50 मंडियों पर काम किया जा रहा है तथा द्वितीय चरण में 38 कृषि उपज मंडी की घोषणा होगी और इस चरण में ही सराड़ा में भी आमदनी तथा क्षेत्रफल देखते हुए कृषि उपज मंडी बनाने की घोषणा की जाएगी।
- उन्होंने बताया कि चावंड गौण मंडी वर्ष 1979 में घोषित की गई थी। इसकी ज़मीन अब तक आवंटित नहीं हुई है, जो प्रक्रियारत् है। उन्होंने कहा कि भूमि प्राप्त होते ही चावंड में भी गौण मंडी बनवा दी जाएगी।
- इससे पहले कृषि विपणन राज्य मंत्री ने विधायक अमृतलाल मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि विधानसभा क्षेत्र सलुम्बर के उपखंड सराड़ा में कृषि उपज मंडी की घोषणा बजट वर्ष 2020-21 में नहीं की गई थी। यद्यपि बजट वर्ष 2020-21 में गौण मंडी सलूम्बर को स्वतंत्र मंडी बनाने की घोषणा की है।

क्विक रिस्पांस टीम के लिये वन विभाग जारी करेगा एसओपी

चर्चा में क्यों ?

19 फरवरी, 2023 को उत्तराखंड के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक डॉ. समीर सिन्हा ने बताया कि प्रदेश का वन महकमा क्यूआरटी (क्विक रिस्पांस टीम) के लिये पहली बार मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करेगा। इसका खाका तैयार किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक डॉ. समीर सिन्हा ने बताया कि क्यूआरटी के लिये मानक संचालन प्रक्रिया के तहत क्यूआरटी में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिये नियम-कायदे तय किये जाएंगे। इसके साथ ही वन्यजीवों द्वारा फसलों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिये भी कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिये क्यूआरटी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन अभी तक इसकी कोई एसओपी जारी नहीं की गई है। टीम में शामिल कर्मचारियों के लिये नियम-कायदे भी नहीं बने हैं।
- डॉ. समीर सिन्हा ने बताया कि टीम को क्या-क्या सुरक्षा उपकरण दिये जाएंगे, टीम में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, उनका कार्यक्षेत्र कितना होगा जैसे तमाम बिंदुओं को शामिल कर एसओपी जारी की जाएगी। इसके साथ ही उन्हें नियमित ट्रेनिंग दिये जाने का भी प्रस्ताव है।
- उन्होंने बताया कि मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिये स्थानीय समुदाय के सहयोग से ग्राम स्तरीय प्राइमरी रिस्पांस टीम (पीआरटी) के गठन की कवायद भी वन विभाग की ओर से की जा रही है।

राज्य सरकार ने दी चार नई नीतियों को मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

20 फरवरी, 2023 को उत्तराखंड के उद्योग मंत्री चंदन राम दास ने देहरादून में विधानसभा स्थित कार्यालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में बताया कि प्रदेश में रोज़गार देने में एमएसएमई की भूमिका अहम है। इस देखते हुए राज्य सरकार ने चार नई नीतियों को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- इस बैठक में उद्योग मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 200 करोड़ से अधिक निवेश वाले उद्योगों को सरकार 10 साल के भीतर पूंजी निवेश पर छूट देगी।
- इसके अलावा स्टार्टअप योजनाओं के लिये 40 करोड़ रुपऐ के बजट का प्रावधान किया जाएगा। नए उद्यमियों को सरकार हरसंभव सहायता देगी।
- मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना, मुद्रा तथा स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री नैनो योजना, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन योजना के तहत शत-प्रतिशत रोज़गार देने का लक्ष्य हासिल किया गया।

नोट :

- उद्योग मंत्री चंदन राम दास ने अफसरों को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री नैनो स्वरोज़गार योजना के मानकों में संशोधन किया जाए। निजी औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिये निवेशक के पास अपनी ज़मीन होनी चाहिये, जिसमें सरकार बुनियादी ढाँचा विकसित करने के लिये अनुदान देगी।
- उन्होंने बताया कि निजी औद्योगिक क्षेत्र में लॉजिस्टिक पार्क, वेयरहाउस, कोल्डस्टोर, ट्रक टर्मिनल बनाने के लिये अनुदान दिया जाएगा।
- प्रदेश में बंद हुए 350 प्लास्टिक उद्योगों को दोबारा शुरु कर प्लास्टिक विकल्प के रूप में नया कारोबार करने के लिये सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- विदित है कि सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित होने से उत्तराखंड में प्लास्टिक विनिर्माण करने वाले 350 उद्योग बंद हुए थे।

भारत-उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास 'दुस्तलिक' पिथौरागढ़ में शुरू

चर्चा में क्यों ?

20 फरवरी, 2023 को भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'दुस्तलिक'का चौथा संस्करण उत्तराखंड के विदेशी प्रशिक्षण नोड, पिथौरागढ़ में शुरू हुआ।

प्रमुख बिंदु

- संयुक्त सैन्य अभ्यास 'दुस्तलिक' में उज्बेकिस्तान और भारतीय सेना के 45-45 सैनिक भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देना है। इस अभ्यास में भारतीय सेना की टुकड़ी में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट की एक इंफैंट्री बटालियन के सैनिक शामिल हैं।
- विदित है कि इस अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था।
- 14 दिनों तक चलने वाला यह संयुक्त अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के मेंडेट के अंतर्गत पर्वतीय और अर्ध-शहरी इलाकों में आतंकवाद विरोधी संयुक्त अभियानों पर ध्यान केंद्रित करता है और इसमें फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास, युद्ध चर्चाएँ, व्याख्यान, प्रदर्शन शामिल होंगे तथा एक सत्यापन अभ्यास के साथ इसका समापन होगा।
- दोनों पक्ष संभावित खतरों को बेअसर करने के लिये संयुक्त रूप से सामरिक अभ्यासों की एक श्रृंखला में ट्रेनिंग, प्लानिंग और निष्पादन करेंगे। इसके अलावा संयुक्त ऑपरेशन करने के लिये नई पीढ़ी के उपकरणों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना भी सीखेंगे।
- इस अभ्यास के दौरान जो दोस्ती, सह-भाव और सद्भावना पैदा होगी, वह विभिन्न अभियानों के संचालन की कार्यप्रणाली को समझने में और एक-दूसरे के संगठन की समझ को सक्षम करके, दोनों सेनाओं के बीच संबंधों को और मज़बूत करने के मामले में एक लंबा रास्ता तय करेगी।

गोवा-केरल की तर्ज पर उत्तराखंड में तैयार होगा पर्यटन पुलिस का ढाँचा

चर्चा में क्यों ?

21 फरवरी, 2023 को उत्तराखंड के पुलिस प्रवक्ता व एडीजी वी. मुरुगेशन ने बताया कि प्रदेश में जल्द ही गोवा और केरल की तर्ज पर पर्यटन पुलिस का गठन किया जाएगा। इसके लिये एक नया सिलेबस तैयार किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- पुलिस प्रवक्ता व एडीजी वी. मुरुगेशन ने बताया कि उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश है। यहाँ पर बहुत से शहर ऐसे हैं जहाँ पर वर्षभर करोड़ों लोग पर्यटन और तीर्थाटन के लिये आते हैं। इनसे संवाद स्थापित करने और परेशानियों को दूर करने के लिये पर्यटन पुलिस की ज़रूरत पर बल दिया जा रहा है।
- उन्होंने बताया कि पिछले साल पर्यटन मंत्रालय की ओर से दिशा-निर्देश जारी हुए थे। इसमें सभी राज्यों को अपने यहाँ सशक्त पर्यटन पुलिस का गठन करने को कहा गया था।

नोट :

- वी. मुरुगेशन ने बताया कि इसके लिये उत्तराखंड पुलिस केरल और गोवा पुलिस के ढाँचे का अध्ययन कर रही है, जिसकी तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी पर्यटन पुलिस का गठन किया जाना है। जल्द ही शासन को पर्यटन पुलिस के ढाँचे के लिये प्रस्ताव भेजा जाएगा। शासन से मंत्रणा के बाद ही यह तय होगा कि ढाँचा कितना बड़ा होगा।
- उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रेनिंग मोड्यूल भी इसी तरह से तय किया जाएगा कि उससे उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- पर्यटन पुलिस को उन शहरों में स्थायी पोस्टिंग दी जाएगी, जहाँ पर वर्षभर पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है। इन पुलिस के जवानों को एक पर्यटन गाइड की तरह प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- पुलिस प्रवक्ता व एडीजी ने बताया कि पुलिस केवल पर्यटकों की कानून-व्यवस्था के तहत ही मदद नहीं करेगी, बल्कि उनकी गाइड की तरह मदद की जाएगी। इसके लिये पुलिसकर्मियों को राज्य के इतिहास, भूगोल की जानकारी भी दी जाएगी। उन्हें यहाँ के महत्त्वपूर्ण स्थलों, मंदिरों आदि के बारे में बारीकी से बताया जाएगा।

'मुख्यमंत्री उत्थान' और 'ज्ञानकोष योजना'

चर्चा में क्यों ?

20 फरवरी, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रदेश में छात्रों को आईएएस-पीसीएस समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये अब मुफ्त कोचिंग मिलेगी। इन परीक्षाओं की तैयारी के लिये 'मुख्यमंत्री उत्थान' और 'ज्ञानकोष योजना' शुरू करने की घोषणा की गई है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री उत्थान योजना के तहत राज्य में छात्रों को आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग दी जाएगी। इससे आर्थिक अभाव की वजह से इन परीक्षाओं की तैयारी न कर पाने वाले छात्र-छात्राओं के लिये सुविधा होगी।
- उन्होंने बताया कि इन छात्रों को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, ऑफलाइन कक्षाएँ परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम, प्रश्न बैंक आदि सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।
- 'ज्ञानकोष योजना' के तहत विभागीय छात्रावास, आश्रम पद्धति विद्यालयों और विभागीय प्रतिष्ठानों का उपयोग करते हुए हर ज़िले में समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना, पुस्तकालयों का उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा, छात्र, शिक्षक एवं समुदाय के सदस्य कर सकेंगे।
- पुस्तकालयों में योग्य अनुभवी और प्रोफेशनल व्याख्याताओं को सूचीबद्ध करते हुए एक संपर्क केंद्र बनाया जाएगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विषयगत समस्या को दूर करेंगे तथा पुस्तकालयों के उपयोग के लिये विशेषज्ञों को सूचीबद्ध, पुस्तकों की व्यवस्था, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि की समीक्षा विशेषज्ञ समिति की ओर से की जाएगी।

अनमैंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर

चर्चा में क्यों ?

22 फरवरी, 2023 को उत्तराखंड के पुलिस संचार एडीजी अमित सिन्हा ने बताया कि प्रदेश में उड़ने वाला हर ड्रोन अब पुलिस की नज़रों के सामने रहेगा। इसके लिये पुलिस अब अनमैंड ट्रैफिक मैनेजमेंट (यूटीएम) सॉफ्टवेयर तैयार करा रही है।

प्रमुख बिंदु

- पुलिस संचार एडीजी अमित सिन्हा ने बताया कि अनमैंड ट्रैफिक मैनेजमेंट (यूटीएम) सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिये दिल्ली की एक कंपनी से करार किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर पर प्रत्येक ड्रोन संचालकों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। पुलिस इस सॉफ्टवेयर का अगले सप्ताह ट्रायल करेगी।

नोट :

- दिल्ली की यह कंपनी पुलिस के लिये यूटीएम सॉफ्टवेयर विकसित कर रही है। इस पर हर ड्रोन को पंजीकृत किया जाएगा। इससे टेक ऑफ होने से लेकर रूट और लैंडिंग तक की लाइव लोकेशन पता चल जाएगी। यदि कोई ड्रोन बिना पंजीकरण उड़ाया जा रहा है तो उसे जैमर से जाम भी कर दिया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर पर मालवाहक ड्रोन से लेकर शौकिया ड्रोन उड़ाने वालों को भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- गौरतलब है कि प्रदेश में अभी तक कौन, कहाँ और क्यों ड्रोन उड़ा रहा है, इस पर नज़र रखने के लिये पुलिस के पास कोई तंत्र नहीं है, जबकि, प्रदेश के कई हिस्सों में छोटे मालवाहक ड्रोन भी उड़ाए जा रहे हैं। इनसे दवाएँ, ब्लड सैंपल और तमाम तरह की सामग्रियों को दूर-दराज के इलाकों में पहुँचाया जा रहा है। ऐसे में कुछ असामाजिक तत्त्व इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं।
- वर्तमान में डीजीसीए ने ड्रोन के लिये यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईएन) जरूरी कर दिया है। अब हर ड्रोन का यूआईएन नंबर जारी होता है। पुलिस यह नंबर अपने सॉफ्टवेयर में फीड करेगी। इसके माध्यम से पुलिस को उसकी लोकेशन का पता चल सकेगा। पुलिस का यह सॉफ्टवेयर नो परमिशन नो टेकऑफ के आधार पर काम करेगा।
- पिछले साल तक आने वाले ड्रोन में यूआईएन नहीं होता था। इसमें आरआईडी (रिमोट आईडेंटिफिकेशन) होता था। आरआईडी रजिस्टर्ड करने के साथ-साथ पुलिस इन ड्रोन में विशेष चिप लगाएगी। यह चिप लोकेशन बताने के लिये लगाई जाएगी।

उत्तराखंड के दो सिपाहियों को मिला प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक

चर्चा में क्यों ?

22 फरवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड पुलिस के दो सिपाहियों फैज़ान अली और राजेश कुँवर को प्रधानमंत्री रक्षा पुलिस पदक से नवाज़ा गया है। उन्हें यह पदक मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल के हाथों से दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- दोनों सिपाहियों ने वर्ष 2019 में रायपुर स्थित एक घर में पार्क कार में आग लगने से फँसे परिवार के छह लोगों को बचाया था।
- राज्य के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि 13 से 17 फरवरी तक मध्य प्रदेश के भोपाल में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान ही दोनों सिपाहियों को पदक देने की घोषणा की गई थी।
- उल्लेखनीय है कि 5 जुलाई, 2019 की रात देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र के दशमेश विहार कॉलोनी के एक घर पर कार में आग लग गई थी। सूचना पर चीता ड्यूटी में नियुक्त कांस्टेबल फैज़ान अली और कांस्टेबल राजेश कुँवर तत्काल वहाँ पहुँचे। कांस्टेबल फैज़ान और राजेश ने जान की परवाह किये बिना अपनी सूझबूझ से छह लोगों की जिंदगी बचाई।

यमुनोत्री रोप-वे निर्माण के लिये हुआ अनुबंध

चर्चा में क्यों ?

23 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की उपस्थिति में यमुनोत्री रोप-वे परियोजना के लिये प्रदेश के पर्यटन विभाग और निजी निर्माण कंपनी 'एसआरएम इंजीनियरिंग एवं एफआईएल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड'के बीच अनुबंध किया गया।

प्रमुख बिंदु

- प्रस्तावित जानकीचट्टी (खरसाली) से यमुनोत्री धाम के लिये 38 किमी. लंबे रोप-वे निर्माण के लिये वन मंत्रालय से क्लीयरेंस पहले ही मिल चुका है। रोपवे का संचालन पीपीपी मोड पर होगा। इस रोप-वे पर करीब 167 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- इस रोप-वे के बनने से यमुनोत्री धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को छह किमी. पैदल नहीं चढ़ना पड़ेगा। रोप-वे से मात्र 15 से 20 मिनट में यमुनोत्री पहुँच सकेंगे। श्रद्धालुओं को जानकीचट्टी (खरसाली) पैदल मार्ग के जरिये करीब 11 हज़ार फुट की ऊँचाई पर स्थित यमुनोत्री धाम पहुँचने में अभी करीब तीन घंटे का समय लगता है।
- इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रोप-वे परियोजना के बनने के बाद यमुनोत्री धाम अपने शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली से जुड़ जाएगा और श्रद्धालु माँ यमुना के दर्शन के लिये सुगमता से पहुँच सकेंगे और प्रदूषण मुक्त प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ उठा सकेंगे। रोप-वे बनने से श्रद्धालुओं को सुविधा मिलने के साथ ही स्थानीय स्तर पर भी लोगों के रोज़गार के संसाधन बढ़ेंगे।

नोट :

- प्रदेश के पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि 38 किमी. लंबाई का पीपीपी मोड पर बनने वाला यह रोप-वे मोनोकेबल डिटैचबल प्रकार का होगा जिसका निर्माण यूरोपीय मानकों के अनुसार फ्राँस और स्विटजरलैंड की तर्ज पर किया जाएगा।
- पर्यटन सचिव ने बताया कि इस रोपवे की यात्री क्षमता एक घंटे में लगभग 500 लोगों को ले जाने की होगी जबकि एक कोच में एक बार में आठ यात्री जा सकेंगे। रोप-वे का लोअर टर्मिनल खरसाली में 1.787 हेक्टेयर भूमि पर जबकि अपर टर्मिनल 0.99 हेक्टेयर भूमि पर यमुनोत्री में बनाया जाएगा।

उत्तराखंड की चार नदियों में पाँच साल खनन कार्य के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

23 फरवरी, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तराखंड की चार प्रमुख नदियों में अगले पाँच साल के लिये नवीकरण को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड में कुमाऊँ मंडल की चार प्रमुख नदियों गौला, शारदा, दाबका और कोसी में अगले पाँच साल तक खनन कार्य के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति मिल गई है। इससे नदियों से खनन सामग्री तो मिलेगी ही, साथ ही इस कारोबार से जुड़े 50 हज़ार स्थानीय लोगों व श्रमिकों को रोज़गार भी मिलेगा।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले दिनों जब दिल्ली में थे तब उन्होंने यह मसला केंद्रीय मंत्री के समक्ष उठाया था। मुख्यमंत्री के मुताबिक, सिविल निर्माण कार्यों, धार्मिक व सामरिक रूप से आवश्यक सड़क और रेल नेटवर्क का विस्तार जैसे अति महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये बेहद जरूरी है। इन नदियों से आरबीएम की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
- गौला नदी
  - कुमाऊँ में सोने की खान कहे जाने वाली गौला नदी एक हिमालयी नदी है जो भारत में बहती है। इस नदी का स्रोत पहाड़पानी है और अंतिम बिंदु किच्छा है। इस नदी की लंबाई लगभग 103 किमी. है।
  - गौला नदी उत्तराखंड में सातताल झील से निकलती है। यह काठगोदाम, हल्द्वानी और शाही से होकर बहती है। फिर यह गंगा की एक सहायक नदी रामगंगा नदी में मिल जाती है।
  - मिट्टी के कटाव और वनों की कटाई के परिणामस्वरूप गौला जलग्रहण कई भूस्खलन से प्रभावित हुआ है। साथ ही, पिछले कुछ वर्षों में झरनों के पानी और समग्र वर्षा में कमी आई है, जिससे इसका प्रवाह कम हो गया है। हल्द्वानी के पास मैदान से टकराने के बाद गौला नदी का तल अत्यधिक उत्खनन के कारण मिट्टी के कटाव का सामना कर रहा है।
- शारदा नदी
  - शारदा नदी एक हिमालयी नदी है जो 'काली नदी', 'कुटियांगडी' या 'महाकाली नदी' के रूप में भी जाना जाता है। यह उत्तराखंड से होकर बहती है।
  - शारदा नदी का पारंपरिक स्रोत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में लिपमपियाधुरा है, जो समुद्र तल से 3,600 मीटर (लगभग 11,800 फीट) ऊपर है।
  - इस नदी की लंबाई 252 किमी. और बेसिन क्षेत्र 18,140 वर्ग किमी. है। काली नदी महाकाली नदी की मुख्य धारा है।
- कोशी नदी
  - कोशी नदी, जिसे कोसी या कौशिकी भी कहा जाता है, उत्तर भारत की प्रमुख तथा पवित्र नदियों में से एक हैं। स्कंदपुराण के मानसखंड में इस नदी का उल्लेख कौशिकी के नाम से हुआ है।
  - यह उत्तराखंड के कुमांऊँ क्षेत्र की एक महत्त्वपूर्ण नदी है। यह रामगंगा की सहायक नदी है। नदी के तट पर कैर तथा शीशम के जंगल पाए जाते हैं।
  - कोशी नदी की लंबाई 168 किमी. है तथा इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 346 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैला है।

नोट :

- दाबका नदी
  - दाबका नदी उत्तराखंड में एक धारा है और इसकी ऊँचाई 1,100 मीटर है।
  - कोसी नदी के पूर्व में प्रवाहित यह नदी नैनीताल के गरमपानी नामक स्थान के पश्चिम से निकलकर नैनीताल तथा ऊधम सिंह नगर में बहते हुए बाजपुर के पास राज्य से बाहर निकल जाती है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं की तर्ज पर अब भोजन माताओं को भी मिलेगी सम्मान राशि

चर्चा में क्यों ?

24 फरवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं की तर्ज़ पर अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत् भोजन माताओं को 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति पर सम्मान राशि देने की तैयारी चल रही है। विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है।

प्रमुख बिंदु

- सरकारी स्कूलों में कार्यरत् भोजन माताओं को 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति पर सम्मान राशि देने के लिये पाँच करोड़ रुपए का कॉरपस फंड बनाया जाएगा, जिसके ब्याज से हर साल औसतन सेवानिवृत्त होने वाली 600 भोजन माताओं को 10 से 25 हज़ार रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी।
- गौरतलब है कि महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के तहत कार्यरत् आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं के सेवानिवृत्त होने पर महिला कल्याण कोष से 30 हज़ार रुपए की धनराशि दी जाती है, जबकि सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिये मिड-डे मील बनाने वाली भोजन माताओं के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता।
- विभाग की ओर से भोजन माताओं को सेवानिवृत्ति पर सम्मान राशि देने का जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, वह दो तरह का है।
- पहले प्रस्ताव में बताया गया है कि भोजन माताओं से हर महीने 144 रुपए अंशदान लिया जाए या फिर सरकार की ओर से इसे जमा किया जाए, ऐसा करने से सेवा से हटने पर उन्हें 8654 से लेकर 51923 रुपए की धनराशि मिलेगी।
- दूसरे प्रस्ताव के अंतर्गत भोजन माताओं को 60 साल में सेवानिवृत्त होने पर उन्हें 10 हज़ार रुपए से लेकर 25 हज़ार रुपए तक की धनराशि दी जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में भोजन माताओं को अभी हर महीने 3000 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। इसमें 900 रुपए केंद्र सरकार की ओर से एवं 2100 रुपए राज्य सरकार की ओर से दिये जाते है।
- विभागीय अधिकारियों के मुताबिक 3000 रुपए मानदेय को बढ़ाकर 5000 रुपए किये जाने का केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।

काशी विश्वनाथ की तर्ज पर हरकी पौड़ी कॉरिडोर

चर्चा में क्यों ?

26 फरवरी, 2023 को उत्तराखंड राज्य की धार्मिक नगरी हरिद्वार के ज़िलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर हरिद्वार की हरकी पौड़ी कॉरिडोर को भी विकसित किया जाएगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 में शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिये कैबिनेट ने संवैधानिक मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- ज़िलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि कॉरिडोर के काम अलग-अलग पाँच प्रोजेक्ट में चलेंगे।
- उन्होंने बताया कि कॉरिडोर विकसित करने के लिये आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोसल) बन गई है। मैकेनाइज संस्था कॉरिडोर के कार्यों को अंतिम रूप दे रही है। जल्द ही कॉरिडोर विकसित करने के लिये कंसल्टेंट की नियुक्ति की जाएगी तथा कंसल्टेंट द्वारा कॉरिडोर की डिजाइन और प्लानिंग का कार्य किया जाएगा। इसके बाद कॉरिडोर की डीपीआर बनाई जाएगी।

नोट :

- विनय शंकर पांडे ने बताया कि हरकी पैड़ी कॉरिडोर की डीपीआर बनने के बाद और कॉरिडोर विकसित करने से पहले हरिद्वार में श्रीगंगा सभाव्यापार मंडल, साधु संत, अखाड़ों, मीडिया और समाजसेवियों से विचार-विमर्श किया जाएगा। विचार-विमर्श के बाद कार्य शुरू होगा।
- ज़िलाधिकारी ने बताया कि कॉरिडोर बनाने का मुख्य उद्देश्य हरिद्वार को खूबसूरत बनाना है, न कि लोगों को उजाड़ना। कॉरिडोर विकसित करने के लिये अतिक्रमण को तोड़ा जाएगा।
- उन्होंने बताया कि हरकी पैड़ी पहुँचने के लिये तीन मार्ग पड़ते हैं। भीमगोड़ा, अपर रोड और मोतीबाजार से होकर लोग हरकी पैड़ी पहुँचते हैं। इन मार्गों की दशा और दिशा दोनों सुधारने का कार्य किया जाएगा।
- कॉरिडोर के लिये हरकी पैड़ी, कनखल, सतीकुंड, संन्यास रोड, भूपतवाला क्षेत्र, भारतमाता मंदिर क्षेत्र, मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर आदि को विकसित करने की योजना है।
- हरकी पैड़ी क्षेत्र में काफी कार्य किये जाएंगे। बिजली और पानी की निकासी को भूमिगत किया जाएगा। जगह-जगह फव्वारे और परिदृश्य बनाए जाएंगे।

एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये योजनाओं पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने की तैयारी

चर्चा में क्यों ?

26 फरवरी, 2023 को उत्तराखंड की महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राज्य सरकार एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये एक लाख रुपए तक की योजनाओं पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने की तैयारी में है। विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि महिला दिवस (आठ मार्च) पर इसका एलान हो सकता है।
- एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये एक लाख रुपए तक की योजनाओं पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने से पशुपालन, मत्स्य पालन, कंप्यूटर प्रशिक्षण, मसाला उद्योग, मिलेट्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोज़गार के लिये बढ़ावा मिलेगा।
- रेखा आर्य ने बताया कि प्रदेश की 45 वर्ष तक की ऐसी महिलाएँ, जिसके पति की मौत हो गई है या फिर अविवाहित हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ऐसी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिये यह भी शर्त रखी गई है कि महिलाओं की मासिक आय छह हजार रुपए से अधिक न हो।
- विभागीय अधिकारियों के मुताबिक समाज कल्याण विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में एकल महिलाओं की संख्या साढ़े तीन लाख है। इसमें 45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएँ भी शामिल हैं।
- विदित है कि राज्य में आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं की संख्या डेढ़ से दो लाख के बीच हो सकती है।

उत्तराखंड के ऊर्जा ज़रूरतों के आकलन की जिम्मेदारी अब अमेरिकी संस्था को

चर्चा में क्यों ?

26 फरवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2025 तक ऊर्जा ज़रूरतों के आकलन की जिम्मेदारी अमेरिकी संस्था मैकेंजी को सौंपी है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार ने तय किया है कि राज्य को श्रेष्ठ बनाने के लिये 2025 तक की ऊर्जा ज़रूरतों को भी पूरा करने की आवश्यकता है। लिहाजा, हर क्षेत्र में बिजली की कुल ज़रूरत का आकलन करने की जिम्मेदारी मैकेंजी को दी गई है।
- राज्य सरकार प्रदेश को 2025 तक श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिये प्रयासरत है। ऊर्जा भी इसका अहम हिस्सा है क्योंकि जल विद्युत परियोजनाओं से अपेक्षाकृत बिजली नहीं मिल पा रही है।

नोट :

- अमेरिकी संस्था मैकेंजी प्रदेश के सभी पहलुओं पर बिजली की आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार को रिपोर्ट देगी। संस्था यह भी सुझाएगी कि किस तरह से ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है।
- सरकार ने यह भी तय किया है कि सभी विभाग बताएंगे कि आने वाले समय में कितनी बिजली खपत होगी और वे कितनी बिजली बचाएंगे। बिजली बचाने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं, इसके लिये हितधारकों के साथ एक बैठक हो भी चुकी है।
- सरकार का फोकस है कि विभागों में सौर ऊर्जा जैसे विकल्प तैयार किये जाएँ, ताकि वह अपनी बिजली खुद पैदा करें और खुद इस्तेमाल करें।

प्रदेश में अनाथ बच्चों के लिये बनेगा देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक

चर्चा में क्यों ?

27 फरवरी, 2023 को उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अमर उजाला के इमर्जिंग लीडर्स ऑफ गढ़वाल कार्यक्रम में प्रदेश में अनाथ बच्चों के लिये देश के पहले सरकारी मदर मिल्क बैंक बनाए जाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि योजना के तहत धात्री महिलाएँ इस बैंक में दूध दान कर सकेंगी। शुरुआत में राज्य में ऐसा एक बैंक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में यह अपनी तरह का पहला और अलग मिल्क बैंक होगा।
- इस मिल्क बैंक के माध्यम से उन नवजात शिशुओं को दूध उपलब्ध कराया जाएगा, जिनकी माता की प्रसव के दौरान ही मृत्यु हो जाती है।
- डॉ. रावत ने कहा कि प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिये सरकार गर्भवती महिलाओं की संस्थागत डिलीवरी पर फोकस कर रही है। सरकार के प्रयास से जहाँ शिशु मृत्यु दर में उत्तराखंड का देशभर में 32वाँ स्थान था, वहीं आज घटकर 26वाँ स्थान हो गया है। इसे और कम करने के प्रयास जारी हैं।
- सरकार ने गर्भवतियों को निशुल्क अस्पताल लाने-ले जाने की व्यवस्था की है। ऐजा बोई योजना भी चलाई जा रही है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को दो हजार रुपए दिए जाते हैं। 1500 रुपए माताओं के खाने के लिये और पाँच सौ रुपए बच्चे के नामकरण के लिये दिये जा रहे हैं।
- उन्होंने बताया कि शिशु-माता मृत्युदर कम करने के लिये सरकार की ओर से एक और योजना बनाई जा रही है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को 15 दिन पहले होम स्टे में रखा जाएगा। इसके लिये होटल, अस्पताल आदि में व्यवस्था की जाएगी।

नोट :